नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 113
दि. 25.01.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

डिजिटल दुनिया में अब तक की बड़ी सेंधः जीमेल, फेसबुक सहित 14.9 करोड़ खातों के यूजरनेम-पासवर्ड सार्वजनिक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसने दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, याहू और आउटलुक जैसे लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े 14.9 करोड़ से अधिक खातों के यूजरनेम और पासवर्ड लीक हो जाने का दावा किया गया है। साइबर सुरक्षा से जुड़ी इस गंभीर घटना का खुलासा साइबर सुरक्षा फर्म एक्सप्रेसवीपीएन की रिपोर्ट में किया गया है, जिसे शोधकर्ता जेरेमिया फाउलर ने प्रकाशित किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, लीक हुआ यह डाटा लगभग 96 जीबी का है, जिसमें ईमेल आईडी, पासवर्ड और संबंधित खातों में लॉगिन करने के डायरेक्ट लिंक तक शामिल हैं। इस डाटाबेस में जीमेल के करीब 4.8 करोड़ खातों के लॉगिन क्रेडेंशियल पाए गए हैं, जबकि फेसबुक के 1.7 करोड़, इंस्टाग्राम के 65 लाख, नेटफ्लिक्स के 34 लाख, याहू के 40 लाख और आउटलुक के 15 लाख खातों की संवेदनशील जानकारी भी इसमें शामिल है। इतनी बड़ी संख्या में खातों का डाटा एक साथ लीक होना अब तक के सबसे बड़े साइबर सुरक्षा जोखिमों में से एक माना जा रहा है।

जेरेमिया फाउलर के अनुसार, सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह डाटाबेस न तो पासवर्ड से सुरक्षित था और न ही किसी तरह से एन्क्रिप्ट किया गया था। यानी इंटरनेट पर मौजूद इस डाटाबेस तक पहुंच रखने वाला कोई भी व्यक्ति बिना किसी

रोक-टोक के लाखों यूजर्स के निजी लॉगिन क्रेडेंशियल देख और इस्तेमाल कर सकता था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह डाटा दुनिया के अलग-अलग देशों के पीड़ितों से एकत्र किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है।

इस लीक हुए डाटा में केवल सोशल मीडिया और ईमेल अकाउंट्स तक सीमित जानकारी नहीं है, बल्कि आशंका जताई गई है कि इसमें बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड और यहां तक कि क्रिप्टो वॉलेट से जुड़े लॉगिन क्रेडेंशियल भी शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा है, तो यह मामला केवल डिजिटल निजता का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर लोगों की आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ जाता है। साइबर अपराधी इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल कर न केवल ऑनलाइन धोखाधड़ी कर सकते हैं, बल्कि लोगों की मेहनत की कमाई भी चुटकियों में गायब कर सकते हैं।

रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि लीक हुए डाटा में कई देशों के '.gov' डोमेन से जुड़े क्रेडेंशियल शामिल हैं। यह पहलू सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे लॉगिन का इस्तेमाल कर हैकर्स सरकारी नेटवर्क में घुसपैठ कर सकते हैं या संवेदनशील सूचनाओं की जासूसी कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकारी ईमेल और सिस्टम से जुड़े पासवर्ड गलत हाथों में चले जाते हैं, तो इसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा तक पर पड़ सकता है।

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के बड़े डाटा लीक के बाद आम यूजर्स के सामने कई तरह के खतरे खड़े हो जाते हैं। अपराधी आपकी लीक हुई जानकारी का इस्तेमाल कर आपके नाम पर फर्जी गतिविधियां कर सकते हैं। आपको ऐसे ईमेल या मैसेज मिल सकते हैं, जो बिल्कुल असली लगें, क्योंकि भेजने वालों के पास आपकी सही और निजी जानकारी होती है। इसके अलावा, चूंकि अधिकांश लोग अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एक ही या मिलता-जुलता पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एक अकाउंट का पासवर्ड लीक होने से हैकर्स आपके दूसरे जरूरी अकाउंट्स, जैसे बैंक या डिजिटल वॉलेट, तक भी आसानी से पहुंच बना सकते हैं।

फाउलर ने चेतावनी दी है कि इतनी बड़ी संख्या में यूनिक लॉगिन और पासवर्ड के सार्वजनिक हो जाने से करोड़ों लोगों के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा हो गया है, जिनमें से कई को शायद यह भी पता न हो कि उनकी निजी जानकारी पहले ही लीक हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि डिजिटल दुनिया में सतर्कता और मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुके हैं।

खैर की लकड़ी तस्करी पर ईडी का बड़ा वार, 11.3 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त

(जीएनएस)। पंचमहल। गुजरात में खैर की लकड़ी की अवैध तस्करी के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कड़ा कदम उठाते हुए करीब 11.3 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई पंचमहल जिले के गोधरा क्षेत्र में सक्रिय एक संगठित तस्करी रैकेट के खिलाफ की गई है, जिसने वर्षों से वन संपदा को नुकसान पहुंचाकर भारी मुनाफा कमाया। ईडी अधिकारियों ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि यह कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है।

ईडी की जांच में सामने आया है कि यह रैकेट गुजरात के विभिन्न जिलों में फैले वन क्षेत्रों और वन्यजीव अभयारण्यों से खैर के पेड़ों की अवैध कटाई में संलिप्त था। आरोप है कि मुख्य आरोपी मुश्ताक आदम तसिया और मोहम्मद ताहिर हुसैन सहित उनके सहयोगियों ने तापी, सूरत, वलसाड, नवसारी, नर्मदा और अन्य जिलों के संरक्षित वन क्षेत्रों में बिना किसी वैध अनुमति के खैर के पेड़ काटे। इसके बाद इस लकड़ी को बाजार में खपाकर भारी मात्रा में अवैध आय अर्जित की गई।

खैर की लकड़ी की मांग देश और विदेश दोनों बाजारों में काफी अधिक मानी जाती है।

यह लकड़ी अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जानी जाती है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसके औषधीय गुणों के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहीं रंगाई उद्योग और पान में प्रयुक्त कत्था बनाने के लिए भी खैर की लकड़ी प्रमुख स्रोत मानी जाती है। इसी बढ़ती मांग का फायदा उठाकर तस्करों ने वन संपदा को निशाना बनाया और सरकारी नियमों को दरकिनार कर अवैध कटाई को अंजाम दिया।

ईडी के अनुसार, इस मामले में पहले से दर्ज वन अपराधों और अन्य एजेंसियों की जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की विस्तृत पड़ताल की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि अवैध रूप से अर्जित धन को विभिन्न अचल संपत्तियों में निवेश किया गया था, ताकि उसकी असली पहचान छिपाई जा सके। इन संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद ईडी ने कुल 11.3 करोड़ रुपये मूल्य की 14 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ये सभी संपत्तियां गोधरा जिले में स्थित बताई गई हैं।

अधिकारियों का कहना है कि कुर्क की गई संपत्तियों में जमीन, मकान और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें तस्करी से हुई कमाई से खरीदा गया था। ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआती कदम है और जांच आगे भी जारी रहेगी। यदि जांच में और संपत्तियों या बैंक खातों का पता चलता है, तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वन विभाग और जांच एजेंसियों का मानना है कि खैर की अवैध कटाई से न केवल पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है, बल्कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संरक्षित वन क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा मानी जाती हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले ने यह भी उजागर किया है कि कैसे संगठित गिरोह स्थानीय स्तर पर नेटवर्क बनाकर वन संपदा का दोहन करते हैं और उससे अर्जित धन को वैध दिखाने की कोशिश करते हैं।

ईडी की इस कार्रवाई को अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कुर्की से न केवल आरोपियों की आर्थिक कमर टूटेगी, बल्कि भविष्य में ऐसे अपराधों में शामिल होने वालों के लिए भी यह एक चेतावनी साबित होगी। सरकार और जांच एजेंसियां लगातार यह संकेत दे रही हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन और उससे जुड़े धन शोधन के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

फिलहाल, इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और ईडी की जांच के दायरे में और नाम सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। अधिकारियों का कहना है कि वन संपदा की रक्षा और अवैध कमाई पर शिकंजा कसने के लिए ऐसे अभियानों को और तेज किया जाएगा, ताकि पर्यावरण और कानून दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में बड़ी राहत, यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने निर्माणाधीन दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन या उससे अधिक चौड़ा किए जाने की अवधि के दौरान टोल टैक्स में 70 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब ऐसे मार्गों पर यात्रियों को निर्धारित टोल शुल्क का केवल 30 प्रतिशत ही चुकाना होगा। सरकार का यह कदम निर्माण कार्य के दौरान होने वाली असुविधा के बीच आम यात्रियों और व्यावसायिक वाहन चालकों को राहत देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

मंत्रालय की ओर से इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, जिस दिन से किसी दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को चार-लेन या उससे अधिक चौड़ा करने का निर्माण कार्य शुरू होगा, उसी दिन से टोल शुल्क में यह रियायत लागू हो जाएगी और परियोजना पूरी होने तक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान टोल दरों में किसी प्रकार की वार्षिक वृद्धि भी नहीं की जाएगी। आम तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हर वर्ष टोल दरों में 7 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करता है, लेकिन निर्माण कार्य के चलते यात्रियों को अतिरिक्त

बोझ से बचाने के लिए इस वृद्धि को स्थगित कर दिया गया है।

सरकार के इस फैसले का लाभ उन हजारों किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर मिलने की संभावना है, जहां फिलहाल चौड़ीकरण का काम चल रहा है या निकट भविष्य में शुरू होने वाला है। नए नियम न केवल आगामी परियोजनाओं पर लागू होंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर भी प्रभावी होंगे। इससे खास तौर पर उन मार्गों पर सफर करने वालों को राहत मिलेगी, जहां निर्माण के कारण यातायात बाधित रहता है और समय के साथ-साथ ईंधन की खपत भी बढ़ जाती है। सरकार देशभर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारतमाला परियोजना सहित कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं के तहत करीब 25 से 30 हजार किलोमीटर लंबे दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन में बदला जा रहा है। इस पूरे अभियान में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। सरकार का मानना है कि चौड़ी सड़कों के निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

चार-लेन और उससे अधिक चौड़े राजमार्ग बनने से व्यावसायिक वाहनों की औसत गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। फिलहाल जहां मालवाहक वाहनों की औसत रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहती है, वहीं नए कॉरिडोर तैयार होने के बाद यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है। इससे माल ढुलाई का समय घटेगा, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और उद्योगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल ढुलाई की हिस्सेदारी को मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक ले जाना है।

सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि टोल में दी गई यह छूट यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए दी गई है। निर्माणाधीन मार्गों पर अक्सर धीमी गति, जाम और असुविधा का सामना करना पड़ता है, ऐसे में पूरा टोल वसूलना यात्रियों के लिए अनुचित माना जा रहा था। अब सरकार के इस फैसले से लोगों को यह महसूस होगा कि उन्हें असुविधा के बदले कुछ राहत भी मिल रही है।

सरकार ने चार-लेन से छह या आठ-लेन किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भी टोल में छूट का प्रावधान रखा है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई चार-लेन राजमार्ग छह या आठ-लेन में बदला जा रहा है, तो उस अवधि में टोल टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यानी यात्रियों को तय टोल का केवल 75 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा पहले से मौजूद नियम के तहत, किसी टोल रोड की लागत वसूल हो जाने के बाद टोल शुल्क को घटाकर 40 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रावधान भी लागू रहेगा।

जानकारों का मानना है कि यह फैसला न केवल आम यात्रियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रति लोगों के भरोसे को भी मजबूत करेगा। सड़क निर्माण के दौरान असुविधा और टोल वसूली को लेकर अक्सर विवाद होते रहे हैं। अब टोल में दी गई यह राहत ऐसे विवादों को कम करने में सहायक साबित हो सकती है।

कुल मिलाकर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

भारत का अंतरिक्ष भविष्य आकार ले रहा है, 2026 में कई उपग्रह मिशन लॉन्च करेगा इसरो

(जीएनएस)। कोयंबटूर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की तैयारी में है। इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन ने शनिवार को कहा कि एजेंसी वर्ष 2026 में कई महत्वपूर्ण उपग्रह लॉन्च करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने संकेत दिए कि इसरो के पास न केवल सैटेलाइट मिशनों की लंबी सूची है, बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े बड़े कार्यक्रम भी पाइपलाइन में हैं। कोयंबटूर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसरो प्रमुख ने कहा कि वर्ष 2026 इसरो के लिए बेहद व्यस्त और अहम रहने वाला है। उन्होंने बताया कि एजेंसी इस साल और अगले साल कई उपग्रह प्रक्षेपण की तैयारी कर रही है और इस दिशा में बड़े पैमाने पर तकनीकी और वैज्ञानिक काम चल रहा है। नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इन मिशनों को लेकर औपचारिक घोषणाएं की जाएंगी, जिससे देश को इसरो की भविष्य की योजनाओं की स्पष्ट तस्वीर मिल सकेगी।

अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने की बात कही थी, इसरो चेयरमैन ने कहा कि भारत के पास पहले से ही कई बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन तय हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसरो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए हमेशा खुला रहा है और आने वाले समय में भारत वैश्विक अंतरिक्ष अभियानों में एक बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

नारायणन ने बताया कि इसरो न केवल उपग्रह प्रक्षेपण तक सीमित है, बल्कि मानव अंतरिक्ष मिशनों को भी अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है, जो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। इसके साथ ही, चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की दीर्घकालिक योजना भी इसरो के रोडमैप में शामिल है।

इसरो प्रमुख के बयान से यह संकेत मिलता है कि गगनयान मिशन के बाद भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताएं और सुदृढ़ होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करता है, तो यह न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अहम होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी क्षमता और रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगा।

हाल ही में पीएसएलवी-सी62 रॉकेट के तीसरे चरण के दौरान आई तकनीकी गड़बड़ी को लेकर पूछे गए सवाल पर नारायणन ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक इस मामले का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एजेंसी हर मिशन से सीख लेकर अपनी प्रणालियों को और बेहतर बनाती है। इसरो की कार्यशैली हमेशा से ही पारदर्शिता और सुधार पर आधारित रही है, और किसी भी तकनीकी चुनौती को भविष्य के अभियानों के लिए अनुभव के रूप में लिया जाता है।

इसरो चेयरमैन ने छात्र समुदाय को संदेश देते हुए युवाओं से अपने विषयों में गहरी समझ विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि समग्र व्यक्तित्व विकास भी उतना ही जरूरी है। नारायणन के अनुसार, वैज्ञानिक सोच, अनुशासन, टीमवर्क और नवाचार की भावना ही किसी भी युवा को भविष्य का वैज्ञानिक और तकनीकी नेता बना सकती है।

अंतरिक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि इसरो की 2026 की योजनाएं भारत को अंतरिक्ष महाशक्तियों की पंक्ति में और मजबूती से खड़ा करेंगी। उपग्रह संचार, पृथ्वी अवलोकन, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े मिशनों के जरिए न केवल देश की सामरिक और आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि आम लोगों के जीवन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

भारत को मिल सकती है बड़ी व्यापारिक राहत अमेरिका अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने के संकेत

(जीएनएस)। दावोस। भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर एक अहम और सकारात्मक संकेत सामने आया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को हटाया जा सकता है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के दौरान 'पॉलिटिको' को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय कमी की है, जिसे अमेरिका अपनी नीति की बड़ी सफलता के तौर पर देख रहा है। स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया कि भले ही फिलहाल ये टैरिफ लागू हैं, लेकिन इन्हें समाप्त करने के लिए कूटनीतिक रास्ता पूरी तरह खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और रूसी तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में भारत के कदमों को अमेरिका सकारात्मक रूप से देख रहा है। उनके अनुसार, यह बदलाव ही आगे चलकर टैरिफ हटाने का आधार बन सकता है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी कांग्रेस में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और सख्त कार्रवाई से जुड़ा एक प्रस्तावित विधेयक चर्चा में है। इस विधेयक के तहत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक का भारी शुल्क लगाए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। इस संभावित कानून को रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर दो चरणों में टैरिफ लगाए थे। पहली बार 1 अगस्त को भारत-अमेरिका व्यापार घाटे का हवाला देते हुए 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया था। इसके बाद 27 अगस्त को रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया। इन फैसलों से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में कुछ समय के लिए तनाव देखने को मिला था।

हालांकि भारत ने शुरुआत से ही साफ किया है कि उसकी ऊर्जा नीति किसी एक देश के दबाव में तय नहीं होती। भारत सरकार ने 'इंडिया फर्स्ट ऊर्जा नीति' पर जोर देते हुए कहा है कि उसका प्राथमिक उद्देश्य 1.4 अरब नागरिकों के लिए किफायती, सुरक्षित और सतत ऊर्जा उपलब्ध कराना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी हाल में कहा कि भारत अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तावित विधेयक से अवगत है और स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है।

भारत का तर्क रहा है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के दौर में उसे अपने नागरिकों और उद्योगों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी। इसी नीति के तहत भारत ने विभिन्न देशों से तेल और गैस की खरीद को संतुलित करने की कोशिश की है। हालांकि अमेरिकी दबाव और वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते हाल के महीनों में भारत ने रूस से तेल आयात में कटौती भी की है, जिसे अब अमेरिका अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहा है। स्कॉट बेसेंट ने इस बातचीत में यूरोपीय देशों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कई यूरोपीय देश सीधे तौर पर रूस से कच्चा तेल नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन भारत से रूसी कच्चे तेल से बने पेट्रोलियम उत्पाद आयात कर रहे हैं। उनके अनुसार, यह स्थिति विडंबनापूर्ण है क्योंकि इससे अप्रत्यक्ष रूप से रूस को आर्थिक लाभ पहुंच रहा है, जबकि सार्वजनिक रूप से रूस पर प्रतिबंधों की बात की जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका वास्तव में भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटाता है, तो इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। साथ ही, यह कदम भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में भी अहम माना जाएगा।

नवसर्जन संस्कृति हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

अर्थव्यवस्था व सेहत पर घातक असर

दावोस में हाल ही में संपन्न वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा के दौरान यह बात शिद्दत से उठी कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ के मुकाबले प्रदूषण ज्यादा घातक असर दिखा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और आईएमएफ की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने इकोनॉमिक फोरम में चर्चा के दौरान कहा कि व्यापार बढ़ाने की कवायद में अकसर व्यापारिक बाधाओं और नियमों की बात की जाती है, लेकिन आर्थिक तरक्की में बाधक प्रदूषण जैसे घटकों की चर्चा कम ही होती है। चर्चा में भारत में प्रदूषण की भयावहता का जिक्र करते हुए कहा गया कि भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुकाबले प्रदूषण का असर ज्यादा घातक व दूरगामी है। फोरम में साल 2022 में विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला दिया गया कि भारत में हर साल सत्रह लाख लोगों की मौत प्रदूषण से हो जाती है। ये आंकड़ा भारत में मरने वालों का अट्ठारह फीसदी बैठता है। जो कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के साथ ही बहुमूल्य जीवन भी लीलता है। कमोबेश यह घातकता जीडीपी पर भी असर डालती है। निस्संदेह, प्रदूषण से होने वाली मौतों से केवल एक परिवार ही नहीं, पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। देश की श्रम शक्ति का ह्रास होता है और आर्थिकी पर दूरगामी प्रभाव होते हैं। वहीं आर्थिकी पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि प्रदूषण के चलते निवेशकों के भरोसे पर भी दुष्प्रभाव होता है। इससे निवेशकों का आकर्षण कम होता है। निस्संदेह, निवेशक के मन में भय होता है कि यदि वह इसी प्रदूषित वातावरण में रहता है तो यह उसके लिये यह घातक हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि प्रदूषण की भयावह स्थिति दुनिया में किसी भी देश की छवि को नुकसान जरूर पहुंचाती है। जिससे निवेशक बेहतर विकल्प की तलाश में अन्य देशों का रुख कर सकते हैं। ऐसे में प्रदूषण के संकट को युद्धस्तर पर निपटाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

निस्संदेह, भारत में प्रदूषण का संकट एक यथार्थ है। यह भी हकीकत है कि देश के नीति-नियंता प्रदूषण संकट के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। जब-जब प्रदूषण संकट गहराता है तो आग लगने पर कुआं खोदने की कवायद की जाती है। कोर्ट की फटकार व नियामक एजेंसियों की सख्ती के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आता है। लेकिन गीता गोपीनाथ के तर्कों के कुछ अर्धसत्य भी हैं। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली वैश्विक एजेंसियां विकासशील देशों को लेकर अपनी सुविधा के हिसाब से प्रतीक-प्रतिमान गढ़ती रही हैं। आईएमएफ जैसी संस्थाओं को अमेरिकी कूटनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहां तक कि इन संस्थाओं में उच्च पदों पर बैठे भारतीय अधिकारी भी अमेरिका के सुरों में गाते नजर आते हैं। सवाल गोपीनाथ के बयान के समय का भी है जब अमेरिका न केवल भारत पर अन्यायपूर्ण टैरिफ लगा रहा है बल्कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते को भी अपनी शर्तों के अनुरूप अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल, इसके बावजूद यह एक हकीकत है कि हमारे देश में प्रदूषण संकट बड़ा है, जिसे देश के नीति-नियंता गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिसके चलते करोड़ों भारतीयों को अपनी जमा-पूंजी अपने व परिवार के उपचार में खर्च करनी पड़ती है। निस्संदेह, प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानूनों को सरल बनाने की भी जरूरत है ताकि उन पर अमल आसानी से हो सके। इसके अलावा लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है कि देश की आबोहवा सुधारने के लिये उन्हें भी कुछ त्याग करने होंगे। उन्हें अपनी विलसिता की जीवन शैली में बदलाव लाकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारना होगा। निश्चित रूप से प्रदूषण को आर्थिक चुनौती के रूप में भी देखने की जरूरत है। खासकर जब भारत खुद को वैश्विक आर्थिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिये प्रयासरत है। हमारा मकसद हो कि हमारे शहर स्वच्छ रहें और नागरिकों के लिये जीवन परिस्थितियां स्वास्थ्य के अनुकूल हों।

UGC Regulations में ऐसा क्या है जिसका सवर्ण कर रहे हैं विरोध? समानता के नियमों को लेकर क्यों मचा बवाल?

> हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026) को अधिसूचित कर दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नए नियमों को लेकर देश में राजनीति तेज हो गई है। इन नियमों के लागू होते ही सवर्ण समुदाय की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी हैं और इसके खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक यह दावा किया जा रहा है कि यह रेगुलेशन एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने के लिए लाया गया है और इसका दुरुपयोग कर छात्रों और शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाएगा। कई मंचों से भय का वातावरण बनाया जा रहा है और तथ्यों से परे जाकर तरह तरह का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भावनात्मक शोर और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर इन नियमों की वास्तविकता को समझा जाए। सवाल उठता है कि आखिर इन नियमों में ऐसा क्या है जिससे कुछ लोग डरे हुए हैं और क्या सचमुच यह किसी समुदाय के खिलाफ हैं? या फिर यह उच्च शिक्षण संस्थानों में लंबे समय से चली आ रही असमानता और भेदभाव की समस्या से निपटने की एक कोशिश मात्र है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और यूजीसी के इन नियमों की सच्चाई आपके सामने रखने की एक कोशिश इस रिपोर्ट के माध्यम से हम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026) को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य परिसर में भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाना और वंचित सामाजिक समूहों को संस्थागत सहारा देना है।

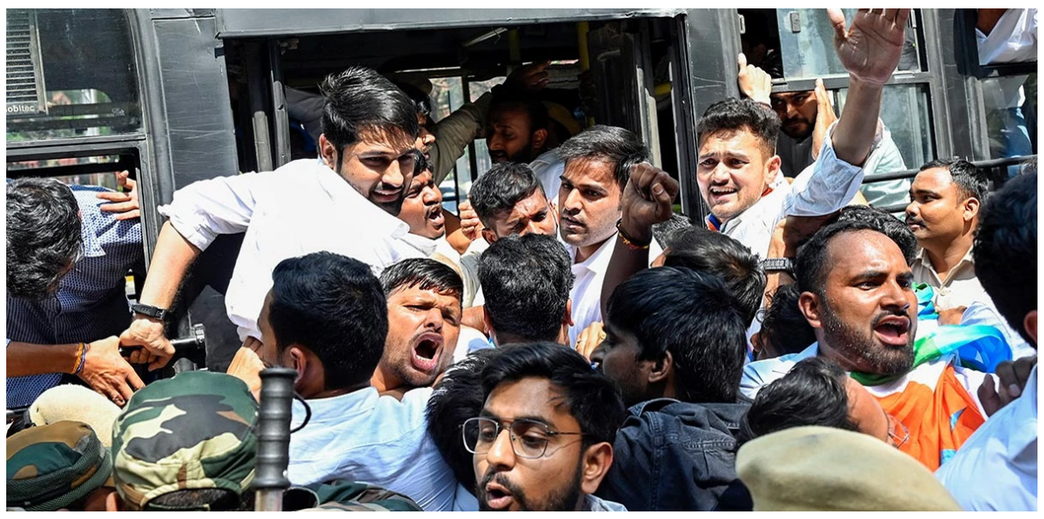

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, नए नियमों के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को समान अवसर केंद्र स्थापित करना अनिवार्य होगा। यह केंद्र न केवल भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा, बल्कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगा। विविधता और समावेशन को बढ़ावा देना भी इसकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। जिन महाविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, वहां यह कार्य संबद्ध विश्वविद्यालय के समान अवसर केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इन नियमों के लागू होने की पृष्ठभूमि में न्यायपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2012 में बने भेदभाव विरोधी नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी को अद्यतन नियम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। यह याचिका रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा दायर की गई थी। हम आपको याद दिला दें कि इन दोनों ही छात्रों के मामलों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न और संस्थागत उदासीनता को लेकर देशव्यापी बहस छेड़ी थी। नए ढांचे के तहत समान अवसर केंद्र के साथ एक समानता समिति का गठन भी अनिवार्य होगा। इस समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और उसे प्रत्येक छह महीने में अपनी रिपोर्ट संस्थान तथा यूजीसी को भेजनी होगी। इसके अतिरिक्त, परिसर में भेदभाव की रोकथाम के लिए छोटी सतर्कता इकाइयों के रूप में समानता दस्तों का गठन भी किया जाएगा।

नियमों में यह भी प्रावधान है कि समान अवसर केंद्र स्थानीय प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समूहों और विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा सके। प्रत्येक संस्थान में एक वरिष्ठ शिक्षक को इस केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया जाएगा, जिसे वंचित समूहों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध माना गया हो। यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो यूजीसी के पास कड़ी कार्रवाई के अधिकार होंगे। इसमें यूजीसी की योजनाओं से वंचित करना, डिग्री और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को रोकना, यहां तक कि संस्थान को यूजीसी की मान्यता सूची से हटाना भी शामिल है।

इस बीच, इन नियमों के लागू होने के साथ ही देश के कुछ हिस्सों में विरोध के स्वर भी सुनाई दिए हैं। आलोचकों का कहना है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि यह कदम लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। हम आपको यह भी बता दें कि आंकड़े दर्शाते हैं कि बीते वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में लगातार वृद्धि हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थीं और एक मजबूत, पारदर्शी तंत्र की जरूरत थी।

देखा जाये तो उच्च शिक्षण संस्थान किसी भी समाज की वैचारिक प्रयोगशाला होते हैं। यदि वही स्थान असमानता और भय के केंद्र बन जाएं, तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। समानता को बढ़ावा देने वाले नए नियम किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे शैक्षणिक तंत्र को अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश हैं। इस पहल को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उन्हें संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से दूर किया जा सकता है। हर नियम का दुरुपयोग संभव है, लेकिन केवल इस भय से सुधारों को रोक देना समाधान नहीं हो सकता। वास्तविक चुनौती यह है कि संस्थान इन प्रावधानों को कागज तक सीमित न रखें, बल्कि ईमानदारी से लागू करें। बहरहाल, यदि ये नियम सही भावना के साथ जमीन पर उतरते हैं, तो यह न केवल वंचित छात्रों और शिक्षकों में भरोसा जगाएंगे, बल्कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएंगे।

प्रेरणा

जब भाग्य मौन होकर अपना निर्णय सुनाता है

गुरु सत्येन्द्रनाथ का आश्रम पहाड़ियों की गोद में बसा था, जहाँ सुबह की हवा में शांति और शाम की नीरवता में गहन चिंतन बसता था। वहाँ आने वाले शिष्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को समझने की दृष्टि पाने आते थे। एक संध्या गुरुजी अपने शिष्यों को जीवन के रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि मनुष्य के जीवन में तीन शक्तियाँ हमेशा आपस में टकराती रहती हैं—दिल, दिमाग और किस्मत। दिल इच्छाओं का संसार रचता है, दिमाग उन इच्छाओं को पूरा करने के उपाय खोजता है, लेकिन किस्मत चुपचाप अपने नियमों के अनुसार अंतिम निर्णय लेती है। जो होता है, वही होता है—चाहे वह हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हो या नहीं।

शिष्यों में से अधिकतर गुरुजी की बातों को श्रद्धा से स्वीकार कर रहे थे, लेकिन सुबोध नाम का एक युवक भीतर ही भीतर असमंजस में था। उसका विश्वास कर्म में था। उसने जीवन में संघर्ष देखा था और यह भी देखा था कि मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। उसे यह विचार पच नहीं रहा था कि भाग्य जैसी कोई शक्ति मनुष्य की योजनाओं और प्रयासों से ऊपर हो सकती है। उसके मन में प्रश्नों का ज्वार उमड़ रहा था। अंततः उसने साहस करके गुरुजी से कहा कि यदि इंसान पूरी लगन से प्रयास करे, तो वह अपनी किस्मत भी बदल सकता है। गुरुजी ने उसकी बात काटी नहीं, न ही कोई तर्क दिया। वे केवल मुस्कराए और उसे अपने साथ चलने का संकेत किया।

दोनों आश्रम से कुछ दूरी पर स्थित एक बड़े बगीचे में पहुँचे। बगीचे में फलदार पेड़ थे, हरियाली थी, लेकिन वातावरण में एक विचित्र-सा तनाव भी था। वहाँ एक जामुन का पेड़ था, जिस पर पके हुए जामुन झूल रहे थे। उसी पेड़ के नीचे एक बंदर था, जो स्पष्ट रूप से भूखा था। उसकी नजरें बार-बार जामुनों पर टिक जातीं। वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही ऊपर बढ़ता, बागबान का मोटा डंडा हवा में लहराने लगता। डर के मारे बंदर नीचे कूद आता। उसने कई बार कोशिश की। कभी तेज़ी से चढ़ा, कभी चुपके से, कभी इधर से तो कभी उधर से। हर बार उसका प्रयास असफल रहा। भूख बढ़ती जा रही थी और निराशा उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी।

सुबोध यह सब ध्यान से देख रहा था। उसे लगा कि यह बंदर उसकी ही तरह है। उसका दिल जामुन चाहता है, उसका दिमाग रास्ते खोज रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं हैं। तभी अचानक बगीचे के दूसरे कोने से एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके हाथ में केले का एक बड़ा गुच्छा था। वह धीरे-धीरे चलते हुए जामुन के पेड़ के पास आया, कुछ क्षण रुका और केले का गुच्छा वहीं जमीन पर रखकर आगे बढ़ गया। उसने बंदर की ओर देखा तक नहीं। बंदर पहले तो सहमा, फिर जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आया, तो वह केले की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने केले देखे, उसकी सारी चिंता जैसे उड़ गई। वह खुशी-खुशी केले छीलने लगा, खाते हुए गर्दन हिलाने लगा और कुछ ही देर में उसकी भूख पूरी तरह शांत हो गई। यह दृश्य सुबोध के मन में गहरे उतर गया। जामुन अब भी पेड़ पर थे, लेकिन बंदर को उनकी आवश्यकता नहीं रही थी। गुरुजी ने धीरे से कहा कि बंदर ने वही किया, जो वह कर सकता था। उसने प्रयास किया, बुद्धि लगाई, लेकिन जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं, तब भी उसे जीवन ने खाली हाथ नहीं लौटाया। जो उसके भाग्य में नहीं था, वह उससे दूर रहा और जो उसके भाग्य में था, वह बिना माँगे उसके सामने आ गया। यही जीवन का सत्य है।

सुबोध के भीतर जैसे कोई परदा हट गया। उसे अपने जीवन की घटनाएँ याद आने लगीं। कितनी बार उसने किसी लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत की थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। और कितनी ही बार ऐसे अवसर मिले थे, जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन फल पर अधिकार समय और भाग्य का होता है। भाग्य का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, बल्कि यह समझना है कि हर प्रयास का परिणाम तुरंत और वैसा ही नहीं मिलता, जैसा हम चाहते हैं।

गुरुजी ने कहा कि जब मनुष्य परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब वह दुखी होता है। अपेक्षाएँ जितनी बड़ी होती हैं, निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। लेकिन जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में हर चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं है, तब वह मानसिक रूप से हल्का हो जाता है। समय कभी किसी के लिए स्थायी नहीं होता। जो आज नहीं मिला, वह कल किसी और रूप में मिल सकता है। और कई बार जो नहीं मिला, वही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होता है।

सुबोध ने गुरुजी के चरणों में सिर झुका दिया। अब उसके मन में विरोध नहीं था, केवल शांति थी। उसने समझ लिया कि दिल की इच्छाएँ और दिमाग की योजनाएँ आवश्यक हैं, लेकिन उन्हें किस्मत की धारा के साथ बहना आना चाहिए। जीवन संघर्ष और समर्पण के बीच का संतुलन है। जब मनुष्य इस संतुलन को सीख लेता है, तब वह हर परिस्थिति में संतोष और सीख दोनों पा लेता है। उस दिन सुबोध ने जाना कि समय का फेर कोई सज़ा नहीं, बल्कि जीवन को समझने का सबसे गहरा पाठ है।

गणतंत्र के 76 वर्ष: संविधान की आत्मा और लोकतंत्र का यथार्थ

प्रतिवर्ष की भांति एक बार फिर गणतंत्र दिवस हमारी राष्ट्रीय चेतना के द्वार पर उपस्थित है। यह दिन प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी के लिए स्वाभाविक रूप से गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत ने औपनिवेशिक दासता से मुक्त होकर अपने ही द्वारा निर्मित संविधान को आत्मसात किया था और स्वयं को प्रभुता संपन्न, सार्वभौमिक, प्रजातंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। यह केवल एक संवैधानिक घटना नहीं थी बल्कि भारत की ऐतिहासिक चेतना, संघर्षशील आत्मा और स्वशासन की आकांक्षा का औपचारिक उद्घोष था। किन्तु इस ऐतिहासिक गौरव के समानांतर एक कड़वा यथार्थ भी हमारे सामने खड़ा है। समय के साथ गणतंत्र दिवस का महान उद्देश्य धीरे-धीरे औपचारिकताओं और रस्म अदायगी तक सीमित होता चला गया है। जिस भावना के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ हुई थी, उसका मूल आशय था कि प्रत्येक नागरिक इस दिन संविधान की गरिमा की रक्षा, राष्ट्रहित के प्रति निष्ठा और देशसेवा के प्रति अपने दायित्वों को न केवल दोहराए बल्कि उन्हें अपने आचरण में भी उतारे। विडंबना यह है कि आज हम इस गौरवपूर्ण अवसर पर संवैधानिक मूल्यों के प्रति संकल्प लेने के बजाय मात्र उन्हें स्मरण कर आत्मसंतोष कर लेते हैं। झंडारोहण, परेड और भाषणों के बाद जैसे हमारे कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व समाप्त हो जाते हैं। गणतंत्र दिवस यदि केवल उत्सव बनकर रह जाए और संवैधानिक चेतना व्यवहार में न उतरे तो यह गणतंत्र की आत्मा के साथ अन्याय ही कहा जाएगा। सही मायनों में गणतंत्र की मूल भावना को हमने आज तक समझा ही नहीं है। 'गणतंत्र' का अर्थ है शासन तंत्र में जनता की भागीदारी। हालांकि हम कह सकते हैं कि शासन तंत्र में जनता को पूर्ण भागीदारी मिली है किन्तु क्या यह वाकई पूर्ण सत्य है? देश का संविधान लागू होने के इन 76 वर्षों में भी क्या वास्तव में शासन तंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है? जनता को यह तो अधिकार है कि मतदान के जरिये वह अपना जनप्रतिनिधि चुने किन्तु एक बार संसद अथवा विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अगले पांच वर्षों तक इन जनप्रतिनिधियों पर उसका क्या कोई अंकुश रह जाता है? वास्तविकता यही है कि इसी प्रावधान का लाभ उठाते हुए राजनीतिक दल देश की जनता का चुनाव के समय महज एक वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं और अपना मतलब निकलने पर जनप्रतिनिधियों पर जनता के दुख-दर्द के बजाय अपने लिए सुख-सुविधाओं का अंबार जुटाने की चिंता सवार हो जाती है और वे इसी कवायद में जुट जाते हैं कि येन-केन-प्रकारेण अगले चुनाव के लिए कैसे करोड़ों रुपयों का इंतजाम किया जाए। अहम सवाल यह है कि जिस राष्ट्र में जनता की भागीदारी चुनाव में सिर्फ वोट डालने और उसके बाद चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आचरण से शर्मसार होकर आंसू बहाने तक ही सीमित रह गई हो, वहां 'गणतंत्र' का भला क्या महत्व रह गया है? खासतौर से ऐसी स्थिति में, जब गरीबी व भुखमरी से त्रस्त करोड़ों लोग चंद रुपयों की खातिर या लाखों लोग महज दो-चार शराब की बोतलों के लिए अपने वोट बेच डालते हों या ईवीएम के दौर में भी कुछ मतदान केन्द्रों पर गुंडागर्दी के बल पर वोट डलवाये जाते हों?

हालांकि इसमें कोई संशय नहीं कि हमें विशुद्ध रूप में एक प्रजातांत्रिक संविधान प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक सम्प्रदाय के लोगों के लिए बराबरी के अधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुछ मूलभूत स्वतंत्रताओं की व्यवस्था भी की गई है, प्रत्येक नागरिक के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है किन्तु गणतांत्रिक भारत में पिछले 76 वर्षों के हालातों का विवेचन करें तो यही पाते हैं कि हमारे कर्णधार एवं नौकरशाह किस प्रकार संविधान के कुछ प्रावधानों के लचीलेपन का अनावश्यक लाभ उठाकर कदम-कदम पर लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार करते रहे हैं। निसंदेह इससे लोकतंत्र की गरिमा प्रभावित होती रही है। संविधान निर्माताओं ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जिन लोगों के कंधों पर संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी होगी, वही इसके प्रावधानों का मखौल उड़ाते नजर आएंगे। ऐसी दयनीय परिस्थितियों को देखकर निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं की आत्मा खून के आंसू रोती होगी।

वक्त-बेवक्त संसद और विधानसभाओं के भीतर होती गुंडागर्दी सरीखी घटनाएं दुनियाभर में हमें शर्मसार करती रही हैं। जिस राष्ट्र में कानून बनाने वाले और देश चलाने वाले लोग ही असभ्य हरकतें करने लगें, वहां अपराधों पर अंकुश लगाने की किससे अपेक्षा की जाए? संसद-विधानसभा सरीखे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिरों में अपराधियों व बाहुबलियों का निर्बाध प्रवेश क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत है? चुनाव जीतने के लिए आज हर राजनीतिक दल में ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करने, चुनाव जीतने के लिए उनका इस्तेमाल करने के अलावा उन्हें ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाकर अपनी सीटें बढ़ाने के फेर में ऐसे दागी लोगों को लोकतंत्र के मंदिरों में प्रवेश दिलाने की होड़ सी लगी है। संसद और विधानसभाओं में धड़ाधड़ प्रवेश पाते अपराधियों का संख्या बल देखें तो यह 'प्रजातंत्र' या 'गणतंत्र' कम, 'अपराधतंत्र' अधिक लगने लगा है। अदालतें जब भी संसद या विधानसभाओं में अपराधिक तत्वों का प्रवेश रोकने की दिशा में कुछ सार्थक पहल करने की कोशिश करती हैं, तमाम राजनीतिक दल उसे संसद के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक दखलंदाजी करार देते हुए हो-हल्ला मचाने लगते हैं।

अभियान

प्रयागराज का माघ मेला: अमृत, समय और मोक्ष की सनातन कथा

भारत की आध्यात्मिक चेतना में कुछ स्थल ऐसे हैं जो केवल भूगोल नहीं, बल्कि जीवित परंपरा होते हैं। प्रयागराज उन्हीं में से एक है, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम केवल नदियों का मिलन नहीं, बल्कि चेतना, कर्म और मोक्ष की त्रिवेणी माना जाता है। इसी पवित्र भूमि पर हर वर्ष माघ मास में जो विराट आध्यात्मिक आयोजन होता है, उसे माघ मेला कहा जाता है। यह मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का विस्तार है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को धोकर आत्मिक शुद्धि की ओर अग्रसर होता है। प्रश्न यह नहीं कि माघ मेला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बल्कि यह है कि यह केवल प्रयागराज में ही क्यों लगता है। इसका उत्तर इतिहास, पुराण, ज्योतिष और भारतीय दर्शन की गहराइयों में छिपा है।

प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है, अर्थात तीर्थों का राजा। यह स्थान वेदों, उपनिषदों और पुराणों में बार-बार वर्णित है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने यहीं प्रथम यज्ञ किया था, इसलिए इसे प्रयाग कहा गया। यज्ञ, दान और तप की भूमि होने के कारण यह स्थान आत्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना गया। गंगा और यमुना का दृश्य संगम तो आंखों से दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती का अदृश्य प्रवाह इस स्थल को रहस्यमय और दिव्य बना देता है। यही अदृश्यता इसे केवल एक भौतिक स्थान नहीं रहने देती, बल्कि इसे चेतना का केंद्र बनाती है। माघ मेला इसी चेतना के पुनर्जागरण का वार्षिक अवसर है।

माघ मास को हिंदू पंचांग में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वह समय होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका होता है और प्रकृति में एक विशेष शुद्ध ऊर्जा का संचार माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस अवधि में जल तत्व अत्यंत सक्रिय होता है और संगम का जल साधारण जल नहीं रह जाता, बल्कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा का वाहक बन जाता है। यही कारण है कि माघ मेले के दौरान संगम में स्नान को मोक्षदायी कहा गया है। यह विश्वास केवल आस्था नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के अनुभव और साधना का निष्कर्ष है।

पौराणिक कथाओं में माघ मेले और प्रयागराज का संबंध अमृत से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन की कथा में बताया गया है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की चार बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, जिनमें से एक बूंद प्रयागराज में गिरी। यही कारण है कि प्रयागराज को अमृत भूमि कहा गया और यहीं कुंभ तथा अर्धकुंभ जैसे महापर्व आयोजित होते हैं। माघ मेला इसी अमृत परंपरा का वार्षिक रूप है, जो हर वर्ष श्रद्धालुओं को अमृतत्व का अनुभव कराने का अवसर देता है।

माघ मेला केवल स्नान तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन शैली का अभ्यास है, जिसे कल्पवास कहा जाता है। कल्पवास का अर्थ है एक निश्चित अवधि तक संसारिक सुविधाओं से दूर रहकर तपस्वी जीवन जीना। कल्पवासी संगम के तट पर कुटिया बनाकर रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, संयमित आहार लेते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और दिन का अधिकांश समय जप, ध्यान और सत्संग में बिताते हैं। यह प्रक्रिया केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म-अनुशासन की प्रयोगशाला है, जहाँ मनुष्य स्वयं को परखता है।

प्रयागराज को ऋषि-मुनियों की तपोभूमि कहा गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भारद्वाज, दुर्वासा, विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों ने यहीं तपस्या की। यह भूमि सदियों से साधना का केंद्र रही है। माघ मेला उसी साधना परंपरा का सामूहिक स्वरूप है, जहाँ साधु-संत, नागा संन्यासी, गृहस्थ और सामान्य श्रद्धालु सभी एक ही उद्देश्य से एकत्र होते हैं, आत्मिक शुद्धि और ईश्वर के निकट जाने के लिए। इस मेले में सामाजिक भेद मिट जाते हैं और हर व्यक्ति केवल साधक बन जाता है।

माघ मेले का सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत की विविध आध्यात्मिक धाराएँ एक साथ दिखाई देती हैं। शैव, वैष्णव, शाक्त, अद्वैत, भक्ति, ज्ञान और कर्म—सभी परंपराएँ संगम तट पर एक-दूसरे से संवाद करती हैं। यह मेला भारत की आध्यात्मिक एकता का जीवंत उदाहरण है। यहाँ प्रवचन होते हैं, कथा होती है, भजन-कीर्तन गूंजते हैं और साधना की सुगंध वातावरण को भर देती है।

हिंदू मान्यताओं में माघ मेले के विशेष स्नान पर्वों का अत्यंत महत्व है। पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर माघी पूर्णिमा तक चलने वाला यह काल आत्मिक साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा जैसे दिनों में संगम स्नान को विशेष फलदायी माना गया है। इन दिनों लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि विश्वास है कि इन तिथियों पर संगम का जल अमृत तुल्य हो जाता है।

साल 2026 में प्रयागराज में माघ मेला 03 जनवरी से प्रारंभ होकर 15 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। यह अवधि केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं, बल्कि साधना का एक पूर्ण चक्र है। इस दौरान संगम क्षेत्र एक अस्थायी आध्यात्मिक नगर का रूप ले लेता है, जहाँ हर दिशा में तप, त्याग और भक्ति की गूंज सुनाई देती है। आधुनिक समय में भी, जब जीवन तेज़ और भौतिक हो गया है, माघ मेला मनुष्य को ठहरकर स्वयं से मिलने का अवसर देता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि माघ मेला प्रयागराज में ही इसलिए लगता है, क्योंकि यह भूमि केवल भौगोलिक संगम नहीं, बल्कि काल, कर्म और चेतना का संगम है। यहाँ स्नान करने का अर्थ केवल शरीर को शुद्ध करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को छोड़ने का संकल्प लेना है। माघ मेला मनुष्य को याद दिलाता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी है। यही कारण है कि सदियों बाद भी माघ मेला अपनी दिव्यता, गरिमा और आध्यात्मिक आकर्षण को बनाए हुए है और हर वर्ष लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ AAP का प्रचंड विरोध

- मणिनगर रेलवे स्टेशन पर AAP अहमदाबाद शहर संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन
- शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार कर भाजपा ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई : AAP का आरोप
- शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाले AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी
- शंकराचार्य का अपमान करने वाली भाजपा का सनातन से कोई लेना-देना नहीं : विजय पटेल AAP
- भाजपा राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि कॉर्पोरेट कंपनी है, जो धर्म का उपयोग करती है : विजय पटेल AAP
- साधु-संतों के अपमान के लिए भाजपा माफी मांगे : विजय पटेल AAP

(जीएनएस)। अहमदाबाद/गुजरात। आम आदमी पार्टी अहमदाबाद शहर समिति द्वारा प्रयागराज में जगद्गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अहमदाबाद शहर अध्यक्ष विजय पटेल, मालधारी सेल प्रदेश अध्यक्ष गुजरात किरण देसाई, ASAP मध्य जोन अध्यक्ष यात्रिक पटेल, ASAP अहमदाबाद शहर अध्यक्ष तीर्थ श्रीमाली, महिला शहर अध्यक्ष सिद्धिबेन भावसार, अहमदाबाद शहर उपाध्यक्ष अल्पेश सोलंकी, अहमदाबाद शहर उपाध्यक्ष दिनेश टांक, अहमदाबाद शहर मंत्री मुकेशभाई, असारवा विधानसभा प्रभारी जगदीश वणजारा, युवा मंत्री अहमदाबाद शहर कश्यप पटेल, थलतेज वार्ड अध्यक्ष चिरागभाई देसाई सहित स्थानीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। इस कार्यक्रम में भाजपा सरकार ने एक बार फिर पुलिस का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की थी। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद शहर अध्यक्ष विजय पटेल ने कहा कि भाजपा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट कंपनी है, जो जरूरत के अनुसार धर्म और साधु-संतों का उपयोग कर सत्ता पर बैठी है, लेकिन वास्तव में भाजपा का सनातन धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदजी के साथ भाजपा प्रशासन ने जिस तरह का व्यवहार किया है वह अत्यंत निंदनीय है,

उनके शिष्यों के साथ भी जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, उसे देखकर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। आज भाजपा को सत्ता का इतना अहंकार हो गया है कि हिंदू परंपरा में सर्वोच्च माने जाने वाले शंकराचार्य से भाजपा, शंकराचार्य होने का प्रमाणपत्र मांगती है, जो अत्यंत निंदनीय है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदजी के साथ हुए इस व्यवहार के लिए भाजपा माफी मांगे, इसी मांग के साथ आज आम आदमी पार्टी अहमदाबाद शहर संगठन द्वारा मणिनगर रेलवे स्टेशन पर प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया गया था।

गुजरात तथा दमण एवं दीव नेवल एरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियल एडमिरल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात तथा दमण एवं दीव नेवल एरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल श्रीतनु गुरु ने शनिवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की।

1995 में भारतीय नौसेना में जुड़े श्रीतनु गुरु नवंबर-2025 से गुजरात तथा दमण एवं दीव नेवल एरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त हुए हैं।

इस मुलाकात के अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार उपस्थित रहे।

बसंत पंचमी पर सूरत में सामाजिक समरसता का उत्सव, अग्रसेन भवन में 11 जोड़ों ने थामा जीवनभर का साथ

(जीएनएस)। सूरत। बसंत पंचमी के पावन और शुभ अवसर पर सूरत में सामाजिक सौहार्द, परंपरा और सेवा भावना का अनुपम दृश्य देखने को मिला, जब 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह पूरे धार्मिक उल्लास और पारंपरिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। परम पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित इस सामूहिक विवाह का आयोजन श्री श्याम प्रचार मंडल महिला इकाई एवं अग्रमिलन महिला इकाई के संयुक्त प्रयास से किया गया। सिटीलाइट क्षेत्र स्थित अग्रसेन भवन के पंचवटी हॉल में आयोजित इस समारोह में मंगल गीतों की गूंज, वैदिक मंत्रोच्चार और नवदंपतियों के चेहरे पर झलकती खुशी ने पूरे वातावरण को भावविभोर कर दिया।

बसंत पंचमी को ज्ञान, संस्कार और शुभारंभ का पर्व माना जाता है और इसी भाव के अनुरूप इस दिन 11 जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की। विवाह स्थल को पारंपरिक सजावट से सुसज्जित किया गया था, जहां पीले रंग की थीम, पुष्प सज्जा और धार्मिक प्रतीकों ने बसंत पंचमी के उल्लास को और भी जीवंत बना दिया। सुबह से ही विवाह स्थल पर चहल-पहल शुरू हो गई थी। वैवाहिक रस्मों के दौरान ढोल-नगाड़ों और मंगल गीतों की मधुर ध्वनि ने आयोजन को उत्सव का रूप दे दिया।

संस्था के संरक्षक पूरणमल अग्रवाल ने बताया कि सामूहिक विवाह में शामिल सभी 11 जोड़े सूरत और उसके आसपास के क्षेत्रों से थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में समानता, सहयोग और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। सामूहिक विवाह न केवल आर्थिक रूप से जरूरतमंद परिवारों को सहारा देता है, बल्कि समाज में सादगी और संस्कारों के महत्व को भी रेखांकित करता है। उन्होंने इस आयोजन को सामाजिक दायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

संस्था की अध्यक्षा शालू खदरिया ने जानकारी दी कि नवयुगल जोड़ों और उनके परिजनों के लिए सगाई से लेकर विदाई तक की संपूर्ण व्यवस्थाएं संस्था द्वारा की गईं।

श्री कमलनयन बजाज की 111 वीं जयंती पर उनके जीवन और विरासत को समर्पित लघु फिल्म का लोकार्पण

श्री शिशिर बजाज और समस्त बजाज समूह परिवार ने अर्पित की श्रद्धांजलि

(जीएनएस)। मुंबई, 23 जनवरी। भारत के प्रख्यात उद्योगपति और स्वाधीनता सेनानी श्री कमलनयन बजाज की 111वीं जयंती के अवसर पर उनकी गौरवशाली जीवन यात्रा को समर्पित विशेष लघु फिल्म का लोकार्पण उनके सुपुत्र और बजाज फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री शिशिर बजाज द्वारा शुक्रवार, 23 जनवरी, 2026 को किया गया।

बजाज समूह परिवार द्वारा निर्मित और यू-ट्यूब पर उपलब्ध यह विशेष लघु फिल्म श्री कमलनयन बजाज के महान व्यक्तित्व और उनके असाधारण जीवन एवं युग को जीवंत करती है, जिन्होंने बजाज समूह की सच्ची उद्यमशील नींव रखी और भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्मृतिजनक फिल्म श्री कमलनयन बजाज की उस यात्रा को दर्शाती है, जिसमें वे महात्मा गांधी से प्रेरित एक युवा स्वतंत्रता सेनानी से एक दूरदर्शी उद्योगपति और राष्ट्रनिर्माता बने। वे मानते थे कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक पुनीत देशभक्ति कर्तव्य है। 23 जनवरी, 1915 को जमनालाल बजाज और जानकीदेवी बजाज के घर जन्मे कमलनयन बजाज तीन महान व्यक्तित्वों के नैतिक प्रभाव में पले-बढ़े—अपने पिता जमनालाल बजाज, अपने मार्गदर्शक महात्मा गांधी और अपने गुरु आचार्य विनोबा भावे। जीवन में प्रवेश करते समय ही उनके मूल्य स्पष्ट थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने दांडी मार्च में भाग लिया और स्वदेशी व खादी आंदोलनों के प्रारंभिक समर्थक बने। उस

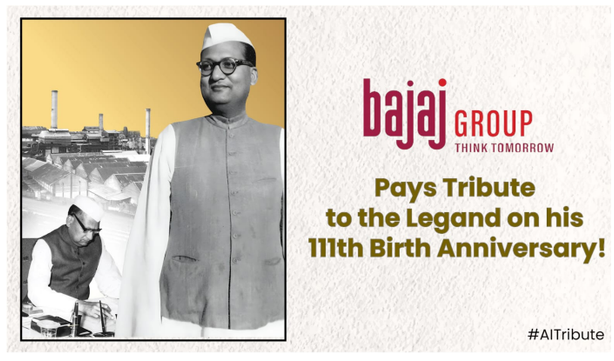

दौर में, जब आर्थिक सशक्तिकरण स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आवश्यक था, वे मानते थे कि उद्देश्य पद या सत्ता से पहले आना चाहिए और उद्यम का लक्ष्य राष्ट्रीय हित की सेवा होना चाहिए। लघु फिल्म यह दर्शाती है कि कैसे कमलनयन बजाज ने सचेत रूप से ऐसे उद्योगों की स्थापना की, जिन्होंने भारत की आयात पर निर्भरता को कम किया और "आत्मनिर्भर भारत" की परिकल्पना को उस समय साकार किया, जब यह शब्द प्रचलन में भी नहीं आया था। अभिलेखीय दृश्यों में उन्हें उत्तर प्रदेश की गोला चीनी मिल का बार-बार दौरा करते हुए दिखाया गया है, जिसे उनके पिता ने चीनी आयात को रोकने के लिए स्थापित किया था। इन दृश्यों में उनका परिवार और उनके छोटे पुत्र शिशिर भी दिखाई देते हैं, जिन्होंने आगे चलकर बजाज हिन्दुस्थान शुगर के बड़े विस्तार का नेतृत्व किया। फिल्म यह भी दर्शाती है कि कैसे उन्होंने उस समय वैश्विक सहयोग स्थापित किये, जब भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमजोर थी। ऐसा ही एक सहयोग बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी फिलिप्स के साथ था और दूसरा इतालवी स्कूटर निर्माता पियाजियो की वेस्पा के साथ, जिससे बजाज का ऑटोमोबाइल व्यवसाय शुरू हुआ। इन अग्रणी साझेदारियों ने कमलनयन बजाज को बजाज समूह का वास्तविक उद्यमी सिद्ध किया, जिन्होंने मूल्य-आधारित विरासत को एक वैश्विक स्तर पर सम्मानित औद्योगिक समूह में रूपांतरित किया। व्यवसाय से परे, कमलनयन बजाज 15 वर्षों तक महाराष्ट्र के वर्धा क्षेत्र से संसद सदस्य रहे और ग्रामीण समुदायों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए स्वयं को समर्पित किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत कार्यों और सांस्कृतिक संस्थानों को सुदृढ़ करने में निरंतर योगदान दिया। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण में भी एक शांत किंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से रियासतों के एकीकरण के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल की सहायता की। इस योगदान का उल्लेख वी.पी. मेनन ने अपनी पुस्तक में किया है। वीडियो में वर्धा स्थित बजाजवाड़ी को भी पुनः दर्शाया गया है, जो सौहार्द, संवाद और राष्ट्रीय सेवा का प्रतीक बन गई थी। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजिनी नायडू, मोरारजी देसाई, खान अब्दुल गफ्फार खान और यहां तक कि नेपाल के राजा-रानी जैसे अनेक नेता आये। सेवाग्राम आश्रम में गांधीजी से मिलने के लिए ये यात्राएँ इतनी नियमित थीं कि महात्मा गांधी ने बजाजवाड़ी को "राष्ट्रीय अतिथि गृह" कहा था। लोकार्पण के इस महत्वपूर्ण अवसर पर बजाज फाउंडेशन के चेयरमैन श्री शिशिर बजाज ने कहा कि मेरे पिता का मानना था कि जो हम बनाते हैं वह टिकाऊ होना चाहिये और जो टिकाऊ हो, उसे समाज की सेवा करनी चाहिये। उनके लिए उद्योग, सार्वजनिक सेवा और सामाजिक संस्थान—तीनों राष्ट्र निर्माण के अविभाज्य स्तम्भ थे। उन्होंने कहा कि यह श्रद्धांजलि हमारी ओर से आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाने का एक विनम्र प्रयास है कि मूल्य- आधारित उद्यमिता व्यवसाय और समाज दोनों को रूपांतरित कर सकती है। फिल्म कमलनयन बजाज के व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रकाश डालती है, जिसमें 19 वर्ष की आयु में सावित्री देवी से उनका विवाह, उनके सभी प्रयासों में उनका अटूट समर्थन और उनके बच्चों द्वारा उनके मूल्यों और दृष्टि को आत्मसात करना मुख्य रूप से शामिल है। उनके बड़े पुत्र राहुल बजाज और छोटे पुत्र शिशिर बजाज ने आगे चलकर उनके द्वारा स्थापित व्यवसायों का उल्लेखनीय विस्तार किया। वर्तमान में यह गरिमापूर्ण विरासत श्री शिशिर बजाज और उनके पुत्रों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। उनके बड़े पुत्र कुशाग्र बजाज, जो वर्तमान में उनके व्यवसाय पक्ष के चेयरमैन हैं, और छोटे पुत्र अपूर्व बजाज। वे कमलनयन बजाज के उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें उद्यम को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ा गया है। बजाज समूह के औद्योगिक विस्तार से लेकर वर्धा, सीकर और ललितपुर में ग्रामीण विकास पहलों को गहराई देने तक, परिवार सामाजिक- आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है। डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जारी यह श्रद्धांजलि फिल्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर अभिलेखीय तस्वीरों को पुनर्स्थापित, सजीव और कथानक रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे इतिहास युवा पीढ़ी के लिए सुलभ बनता है और कमलनयन बजाज के जीवन की गरिमा और गम्भीरता भी बनी रहती है। इस सुरुचिपूर्ण फिल्म का इन हाउस प्रोडक्शन, पटकथा लेखन एवं वॉयस ओवर बजाज समूह की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स महाप्रबंधक सुश्री सुरुचि महतपुरकर कोरे द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जब राष्ट्र श्री कमलनयन बजाज को उनकी 111वीं जयंती पर स्मरण कर रहा है, तब बजाज परिवार की यह सृजनात्मक श्रद्धांजलि एक कालातीत संदेश दोहराती है कि सच्ची उद्यमिता केवल विस्तार से नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा और मूल्यों की संरक्षा से परिभाषित होती है।

बसंत पंचमी पर सेवा और संस्कार का संगम, बैटर टुमारो फाउंडेशन ने 400 से अधिक बच्चों को कराया पौष्टिक भोजन

(जीएनएस)। सूरत। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बैटर टुमारो फाउंडेशन की ओर से मानव सेवा और सामाजिक समर्पण का प्रेरक उदाहरण देखने को मिला, जब संस्था द्वारा संचालित 'नर सेवा नारायण सेवा' पौष्टिक आहार अभियान के तहत सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के लिए भोजन सेवा का आयोजन किया गया। यह सेवा शुक्रवार शाम उधना–मगदल्ला रोड स्थित राधाकृष्ण मंदिर परिसर में संपन्न हुई, जहां श्रद्धा, उत्साह और करुणा का वातावरण पूरे आयोजन के दौरान बना रहा। फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस विशेष आहार सेवा का अवसर बसंत पंचमी के साथ-साथ बाबोसा के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया गया। धार्मिक आस्था और सामाजिक दायित्व के इस संगम ने कार्यक्रम को और अधिक भावनात्मक तथा प्रेरणादायी बना दिया। शाम छह बजे से शुरू हुई इस सेवा में 400 से अधिक बच्चों ने पौष्टिक और संतुलित भोजन ग्रहण किया। भोजन पाने वाले बच्चों के चेहरों पर संतोष और मुस्कान साफ झलक रही थी, जो इस पूरे आयोजन की सार्थकता को दर्शा रही थी। बैटर टुमारो फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि संस्था लंबे समय से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। फाउंडेशन का उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसी सोच के तहत संस्था स्लम क्षेत्रों, वृद्धाश्रमों, भिक्षु गृहों, गौशालाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बस्तियों में नियमित रूप से पौष्टिक आहार सेवा उपलब्ध कराती आ रही है। बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित यह सेवा उसी निरंतर अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी रही।

कार्यक्रम के दौरान बाबोसा का जन्मोत्सव भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। धार्मिक अनुष्ठानों और सेवा कार्य के संयोजन ने उपस्थित लोगों के मन में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को और गहरा किया।

आयोजन स्थल पर स्वयंसेवकों और संस्था के सदस्यों ने पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ सेवा कार्य को अंजाम दिया, जिससे बच्चों और उनके अभिभावकों को सम्मानजनक और सुव्यवस्थित वातावरण में भोजन प्राप्त हो सका।

इस अवसर पर बैटर टुमारो फाउंडेशन के संस्थापक चेयरमैन राजेश भारूका और अध्यक्ष सचिन सिंगला विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ संस्था से जुड़े कई सक्रिय सदस्य और समाजसेवी भी आयोजन में शामिल हुए। सुशील मानधनी, धर्मेंद्र भंसाली, गोपाल परतानी, अजय बिदावतका, आलोक अग्रवाल, नरेश सराफ, गोपाल अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों ने सेवा कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने स्वयं भोजन वितरण में सहयोग किया और बच्चों के साथ समय बिताकर आयोजन को केवल औपचारिक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ बना दिया।

फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज में व्याप्त असमानताओं को कम करने के लिए ऐसे सेवा कार्य अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी जरूरतें नहीं पहुंचतीं, तब तक विकास अधूरा है। पौष्टिक आहार सेवा जैसे अभियानों के माध्यम से संस्था बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रही है।

आयोजन के अंत में उपस्थित सदस्यों और स्वयंसेवकों ने इस तरह के सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने समाज के अन्य सक्षम वर्गों से भी आगे आकर ऐसे अभियानों में सहयोग करने की अपील की, ताकि जरूरतमंदों तक सहायता और सम्मान दोनों पहुंच सके। बसंत पंचमी के इस अवसर पर आयोजित यह सेवा न केवल भोजन वितरण का कार्यक्रम रहा, बल्कि यह संदेश भी देता गया कि सच्ची भक्ति और उत्सव वही है, जिसमें मानवता की सेवा शामिल हो।

बर्फ की सफेद चादर में लिपटा चारधाम, हिमस्खलन के बढ़ते खतरे से उत्तराखंड में हाई अलर्ट

(जीएनएस)। देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी ने एक बार फिर पहाड़ी प्रदेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चारधाम सहित ऊपरी हिमालयी क्षेत्र पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर में ढक गए हैं, जिससे न केवल तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, बल्कि हिमस्खलन का खतरा भी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड और खराब मौसम के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, वहीं प्रशासन को आपदा की आशंका के चलते चौबीसों घंटे सतर्क रहना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी जारी रहने की चेतावनी दी है, जिससे हालात और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

रक्षा भू-सूचना अनुसंधान संस्थान (डीजीआरई) की ओर से जारी ताजा चेतावनी ने चिंता और बढ़ा दी है। संस्थान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में हिमस्खलन का खतरा बेहद अधिक बना हुआ है। इन जिलों को डेंजर लेवल-3 श्रेणी में रखा गया है, जो यह संकेत देता है कि यहां किसी भी समय भारी हिमस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं बागेश्वर जिले को डेंजर लेवल-2 में रखा गया है, जहां भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही बर्फबारी के कारण पहाड़ों की ढलानों पर अस्थिर बर्फ जमा हो गई है, जो थोड़ी सी हलचल या तापमान में बदलाव से खिसक सकती है। चारों धाम—बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री—इन दिनों पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर कई स्थानों पर कई फीट तक बर्फ जम

चुकी है। सड़कों पर फिसलन बढ़ने से वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है और कई इलाकों में संपर्क मार्ग बाधित होने की स्थिति बन गई है। स्थानीय प्रशासन लगातार बर्फ हटाने और मार्गों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लगातार गिरती बर्फ राहत कार्यों में भी बाधा बन रही है। तीर्थस्थलों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग भी घरों में दुबकने को मजबूर हैं।

लगातार बर्फबारी और शीतलहर के चलते प्रदेश के पहाड़ी जिलों में तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया है। कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन जम गई हैं, जिससे लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति भी कई जगह बाधित हुई है, जिससे ठंड के बीच लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए हालात खासे चिंताजनक बने हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। संभावित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दलों को संवेदनशील क्षेत्रों के पास तैनात किया गया है। प्रशासन लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। खासकर हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों, ऊंचाई वाले दर्रों और दुर्गम रास्तों पर जाने से फिलहाल परहेज करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि चेतावनियों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

मौसम की गंभीरता और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के कई जिलों में कक्षा एक से बारह तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। ठंड और बर्फबारी के कारण स्कूलों तक पहुंचना जोखिम भरा हो गया है, ऐसे में यह निर्णय एहतियातन लिया गया है। अभिभावकों ने भी प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया है।

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल राहत के आसार कम हैं और आने वाले कुछ दिनों तक पर्वतीय इलाकों में ठंड और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालयी क्षेत्रों में इस समय मौसम बेहद संवेदनशील बना हुआ है और जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में प्रशासन और आम नागरिकों दोनों को संयम और सतर्कता के साथ हालात का सामना करने की जरूरत है।

बजट: 'विकसित भारत 2047' के रोडमैप पर रहेंगी निगाहें,एक फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अपने कार्यकाल का नौवां बजट

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करने वाला केंद्रीय बजट 2026-27 एक फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का यह नौवां बजट प्रस्तुत करेंगी, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा पूर्ण बजट होगा। इस बजट को 'विकसित भारत 2047' के दीर्घकालिक लक्ष्य की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार की मंशा इस बजट के जरिए आर्थिक विकास को मजबूती देने, राजकोषीय संतुलन बनाए रखने और समाज के हर वर्ग तक विकास के लाभ पहुंचाने की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, बजट की रूपरेखा 'विकसित भारत 2047' के विजन को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। इसमें बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति देने, विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर रहने की संभावना है। इसके साथ ही आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर राहत देने से जुड़े कदम भी बजट का अहम हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से जूझ रही है, भारत के लिए यह बजट स्थिरता और निरंतर विकास का संदेश देने वाला माना जा रहा है। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी, जिसमें सरकार अपनी प्राथमिकताओं और नीतिगत एजेंडे को संसद के सामने रखेगी। इसके अगले दिन 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण

2025-26 पेश किया जाएगा, जो देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, बीते वर्ष के प्रदर्शन, चुनौतियों और आगामी संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। इसके बाद एक फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री का बजट भाषण होगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी।

बजट को लेकर करदाताओं की अपेक्षाएं इस बार भी सबसे अधिक आयकर से जुड़ी हैं। माना जा रहा है कि नई आयकर व्यवस्था में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, मानक कटौती में बढ़ोतरी संभव है और टैक्स स्लैब को लेकर भी राहत की घोषणा हो सकती है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिल सके। वहीं किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा बढ़ाने, कृषि से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, महिला किसानों के लिए विशेष योजनाएं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने जैसे कदम बजट में शामिल हो सकते हैं।

सरकार के एजेंडे में बुनियादी ढांचे का विकास और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देना भी प्रमुख रूप से शामिल है। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और शहरी बुनियादी ढांचे के लिए आवंटन बढ़ाए जाने की संभावना है। इसके साथ ही 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को नई ऊर्जा देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। इन पहलों से न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की भी संभावना बनेगी, जो युवा आबादी वाले देश के लिए बेहद जरूरी है।

शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को लेकर भी बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने, स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने तथा डिजिटल शिक्षा को और व्यापक बनाने पर सरकार का फोकस रह सकता है। इसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करना और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।

केंद्रीय बजट की तैयारी की प्रक्रिया कई महीनों पहले शुरू हो जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से उनके खर्च और राजस्व के अनुमान एकत्र करता है। इसके बाद वित्त मंत्री उद्योग जगत, अर्थशास्त्रियों, कृषि विशेषज्ञों, श्रमिक संगठनों और विभिन्न हितधारकों के साथ प्री-बजट बैठकों के माध्यम से सुझाव लेती हैं। बजट दस्तावेजों की छपाई से पहले पारंपरिक 'हलवा सेरेमनी' का आयोजन किया जाता है, जो बजट की गोपनीयता बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक में 'लॉक-इन' अवधि के दौरान रहकर बजट को अंतिम रूप देते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट दस्तावेजों के लिए पारंपरिक ब्रीफकेस की जगह लाल रंग के बही-खाते का उपयोग शुरू किया है, जो अब बजट प्रस्तुति की एक अलग पहचान बन चुका है। केंद्रीय बजट 2026-27 पूरे वित्त वर्ष के लिए एक पूर्ण बजट होगा और इसका सीधा प्रसारण संसद टीवी के साथ-साथ विभिन्न डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इस बजट के जरिए सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए आर्थिक विकास को नई गति देना और 'विकसित भारत 2047' के सपने को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाना है।

योगीराज में मिटा बीमारू राज्य का धब्बाः अमित शाह

राजधानी में उत्तर प्रदेश दिवस-2026 का भव्य शुभारंभ, विकास और सुशासन पर केंद्रित समारोह

(जीएनएस)। लखनऊ। राजधानी लखनऊ के बसंत कुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर शनिवार को तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस-2026 का औपचारिक और भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को खास बना दिया। मंच से उत्तर प्रदेश की बदली तस्वीर, विकास की तेज रफ्तार, मजबूत कानून-व्यवस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पूरे परिसर में प्रदेश की उपलब्धियों को दर्शाने वाली झांकियां, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत और आधुनिक प्रगति का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक समय जिस प्रदेश को 'बीमारू राज्य' कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास का नया मॉडल बन चुका है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध, अराजकता और निवेश के अभाव से जुड़ी थी, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। कानून-व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, माफिया और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की गई है और निवेशकों का भरोसा प्रदेश पर लगातार बढ़ा है। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योगीराज में उत्तर प्रदेश से बीमारू राज्य का धब्बा मिट चुका है।

अपने संबोधन में अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम होगी। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला यह प्रदेश अगर तेज गति से आगे बढ़ता है, तो भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने प्रदेश की जनता से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा को प्रचंड बहुमत देने की अपील करते हुए कहा कि मजबूत सरकार ही विकास और सुशासन की गारंटी होती है।

अमित शाह ने योगी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सड़क, रेल, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और औद्योगिक गलियारों के निर्माण से प्रदेश का बुनियादी ढांचा पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने बताया कि एक समय जहां निवेशक उत्तर प्रदेश आने से कतराते थे, आज वही प्रदेश निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश ने औसतन करीब 17 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

गृह मंत्री ने 'एक जनपद एक उत्पाद' यानी ओडीओपी योजना को उत्तर प्रदेश की पहचान बदलने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब कई लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन आज यह योजना लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन चुकी है और प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश-दुनिया में नई पहचान दिला रही है। इसी तरह 'एक जिला-एक व्यंजन' योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विविध खाद्य संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

निवेश और उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर यूनिट्स, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक क्लस्टर तेजी से विकसित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश को करीब 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं और उनसे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन को उन्होंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इन आयोजनों से न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली पांच विशिष्ट विभूतियों को 'उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26' से सम्मानित किया गया। इनमें लखनऊ निवासी अंतरिक्ष यात्री एवं भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, प्रयागराज निवासी 'फिजिक्स वाला' के संस्थापक अलख पांडेय, बुलंदशहर निवासी डॉ. हरिओम पंवार, मेरठ की रश्मि आर्य, श्रीमद् दयानंद आर्य कन्या गुरुकुल की संस्थापक तथा वाराणसी निवासी कृषि वैज्ञानिक डॉ. सुधांशु सिंह शामिल रहे। सम्मान प्राप्त करने वाली विभूतियों ने इसे अपने जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताया।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को 'संयुक्त प्रांत' से वर्तमान नाम मिला था। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में हर वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी तीन दिनों तक प्रदेश के सभी जिलों के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों और विदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेशवासियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

डीजीसीए की सख्ती के बाद इंडिगो ने सरेंडर किए 717 स्लॉट, शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में बड़ी कटौती

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की सख्ती के बाद अपने परिचालन में बड़ा बदलाव करना पड़ा है। नियामक के निर्देशों के अनुपालन में इंडिगो ने शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों पर कुल 717 स्लॉट सरेंडर कर दिए हैं। ये स्लॉट जनवरी से मार्च के बीच की अवधि के लिए छोड़े गए हैं। इस कदम को हाल के महीनों में एयरलाइन के बिगड़े परिचालन संतुलन और लगातार सामने आई अव्यवस्थाओं से जोड़कर देखा जा रहा है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिसंबर महीने में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द और विलंबित हुई थीं, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीजीसीए ने इंडिगो की घरेलू उड़ानों में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत एयरलाइन को अपने निर्धारित उड़ान स्लॉट्स में कमी करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप 717 स्लॉट सरेंडर किए गए। यह कदम यह दर्शाता है कि नियामक अब परिचालन अनुशासन को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है।

इंडिगो द्वारा छोड़े गए स्लॉट देश के कुल 16 घरेलू हवाई अड्डों से संबंधित हैं, जिनमें बड़े महानगरों के एयरपोर्ट सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 236 स्लॉट खाली किए गए हैं, जबकि दिल्ली में 150 स्लॉट छोड़े गए। इसके अलावा बेंगलुरु में 84, हैदराबाद में 68 और पुणे में 48 स्लॉट सरेंडर किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, छोड़े गए कुल स्लॉट्स में से 364 स्लॉट देश के छह प्रमुख महानगरों—दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद—से जुड़े हैं। इन स्लॉट्स में मार्च महीने की हिस्सेदारी सबसे अधिक बताई जा रही है, जिससे संकेत मिलता है कि उस अवधि में उड़ानों की संख्या पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

इंडिगो द्वारा स्लॉट छोड़े जाने के बाद अन्य एयरलाइनों के लिए अवसर भी पैदा हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इन स्लॉट्स के अस्थायी उपयोग के लिए अन्य एयरलाइनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। स्लॉट पुनर्वितरण के लिए गठित समिति की पहली बैठक 13 जनवरी को हो चुकी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन स्लॉट्स का उपयोग करते समय एयरलाइनों को अपने मौजूदा रूट बंद नहीं करने होंगे, ताकि यात्रियों को किसी तरह की अतिरिक्त असुविधा न हो और हवाई सेवाओं की निरंतरता बनी रहे।

डीजीसीए के आदेश के बाद इंडिगो की दैनिक घरेलू उड़ानों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है। आमतौर पर इंडिगो प्रतिदिन 2,200 से अधिक उड़ानों का संचालन करती रही है, लेकिन अब यह संख्या घटकर करीब 1,930 प्रतिदिन रह गई है। शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम के तहत पहले एयरलाइन को प्रति सप्ताह 15,014 उड़ानों की अनुमति दी गई थी, जो अब 10 प्रतिशत कटौती के बाद कम हो गई है। इसका सीधा असर उड़ानों की उपलब्धता और कुछ रूट्स पर सीटों की संख्या पर पड़ सकता है।

दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो का परिचालन संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था। 3 से 5 दिसंबर के बीच एयरलाइन को 2,507 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं, जबकि 1,852 उड़ानें निर्धारित समय से विलंबित रहीं। इस अव्यवस्था से देशभर में तीन लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए थे। यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, कई यात्राएं रद्द हुईं और वैकल्पिक व्यवस्थाओं की कमी को लेकर भी शिकायतें सामने आईं। इसी पृष्ठभूमि में डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाते हुए इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।

उड़ान व्यवधानों को गंभीर लापरवाही मानते हुए डीजीसीए ने 17 जनवरी को इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही एयरलाइन को 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने के निर्देश भी दिए गए। नियामक संस्था के अनुसार, उड़ानों में बार-बार हो रहे व्यवधान के पीछे फ्लाइट क्रू की कमी, संचालन प्रबंधन में कमजोरियां, सॉफ्टवेयर से जुड़ी खामियां और नियामकीय तैयारियों की कमी जैसे कारण सामने आए हैं। डीजीसीए ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से समझौता करने वाली किसी भी एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो द्वारा स्लॉट सरेंडर करना न केवल एयरलाइन के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे विमानन क्षेत्र के लिए एक संदेश भी है कि तेजी से विस्तार के साथ-साथ मजबूत परिचालन व्यवस्था और नियामकीय अनुपालन बेहद जरूरी है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि इंडिगो अपनी व्यवस्थाओं को किस हद तक सुधार पाती है और यात्रियों का भरोसा फिर से जीतने में सफल होती है।

दिल्ली पहुंचीं ईयू की शीर्ष नेता उर्सुला वॉन डेर लेन,भारत–यूरोपीय संघ संबंधों में नई गति, गणतंत्र दिवस पर बतौर चीफ गेस्ट होंगी शामिल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंच गई हैं। उनके साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी रविवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे। इस उच्चस्तरीय दौरे को भारत–ईयू संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और भारत व यूरोप दोनों ही एक-दूसरे को भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं।

इस यात्रा का विशेष महत्व इस बात से भी जुड़ा है कि यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगा। यह न केवल भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते आपसी विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक प्रमुख और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। इसके अलावा 27 जनवरी को प्रस्तावित भारत–ईयू शिखर वार्ता में आर्थिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी, रक्षा, तकनीक और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच होने वाली बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु भारत–ईयू मुक्त व्यापार समझौता रहेगा। यह समझौता लंबे समय से बातचीत के दौर में है और अब इसे अंतिम रूप दिए जाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता और स्थिरता लाने के लिए भारत–ईयू आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना जरूरी है। ऐसे में इस शिखर वार्ता के दौरान मुक्त व्यापार समझौते को लेकर कोई ठोस घोषणा या समयबद्ध रोडमैप सामने आ सकता है।

व्यापार के अलावा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी इस दौरे का एक अहम पहलू है। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भारत और यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। माना जा रहा है कि रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचे पर बातचीत होगी, जिससे दोनों पक्षों के बीच तकनीकी सहयोग और संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा मिल सके।

साबरमती में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर अहमदाबाद–विरमगाम रेलखंड में साबरमती ए केबिन (SBT-A) और साबरमती (SBT-E) के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के कमीशनिंग कार्य हेतु 27 जनवरी, 2026 को प्रस्तावित ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

आंशिक रूप से निरस्त ट्रेनें

1.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 20901/20902 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर कैपिटल-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद और गांधीनगर कैपिटल के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

2.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 22926 ओखा–अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस (01-ट्रिप) अपने निर्धारित मार्ग विरमगाम-साणंद-साबरमती(जेल साइड)-अहमदाबाद के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया विरमगाम-कटोसन रोड–कलोल-साबरमती बीजी के रास्ते चलेगी तथा साबरमती बीजी स्टेशन (धरमनगर साइड) पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन साबरमती बीजी(धरमनगर साइड) और अहमदाबाद के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। इस दौरान यह ट्रेन साणंद, साबरमती जं. (जेल साइड) और अहमदाबाद नहीं जाएगी।

पूर्णतः निरस्त ट्रेनें

1.दिनांक 26.01.2026 एवं 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 69185 अहमदाबाद-विरमगाम मेमू निरस्त रहेगी।

2.दिनांक 27.01.2026 एवं 28.01.2026 की ट्रेन संख्या 69186 विरमगाम-अहमदाबाद मेमू निरस्त रहेगी।

3.दिनांक 26.01.2026 एवं 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

4.दिनांक 27.01.2026 एवं 28.01.2026 की ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

5.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 20959/20960 वलसाड–वडनगर-वलसाड इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

1.दिनांक 26.01.2026 को ट्रेन संख्या 19032 योग नगरी ऋषिकेश–साबरमती योगा एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग खोडियार-साबरमती बीजी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया खोडियार–चांदलोडिया–साबरमती 'ए' केबिन के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन साबरमती बीजी (धरमनगर साइड) के स्थान पर साबरमती स्टेशन (जेल साइड) पर जाएगी।

2.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 14807 जोधपुर–दादर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग खोडियार-साबरमती बीजी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया खोडियार–चांदलोडिया–साबरमती 'ए' केबिन–अहमदाबाद के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन साबरमती बीजी (धरमनगर साइड) के स्थान पर साबरमती स्टेशन (जेल साइड) पर ठहराव करेगी।

3.दिनांक 26.01.2026 की ट्रेन संख्या 14805 यशवंतपुर–बाड़मेर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग अहमदाबाद-साबरमती बीजी-खोडियार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया अहमदाबाद–साबरमती 'ए' केबिन–चांदलोडिया–खोडियार के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन साबरमती बीजी (धरमनगर साइड) के स्थान पर साबरमती स्टेशन (जेल साइड) पर ठहराव करेगी।

4.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस–दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग अहमदाबाद-साबरमती बीजी (धरमनगर साइड)-खोडियार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया अहमदाबाद–साबरमती 'ए' केबिन–चांदलोडिया–खोडियार के रास्ते चलेगी।

5.दिनांक 27.01.2026 की ट्रेन संख्या 11089 भगत की कोठी–पुणे एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग खोडियार-साबरमती बीजी (धरमनगर साइड) के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया खोडियार–चांदलोडिया–साबरमती 'ए' केबिन के रास्ते चलेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। यात्री कृपया विस्तृत जानकारी हेतु रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन करें।

इंजीनियरिंग कार्य के चलते कानालुस–पोरबंदर और पोरबंदर–कानालुस लोकल ट्रेनों का संचालन 28 फरवरी तक गोप जाम स्टेशन से होगा

(जीएनएस)। राजकोट मंडल के कानालुस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म मरम्मत कार्य की वजह से 28 फरवरी, 2026 तक कानालुस–पोरबंदर और पोरबंदर–कानालुस लोकल ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

आंशिक रूप से प्रभावित ट्रेनें

ट्रेन संख्या 59206 पोरबंदर–कानालुस लोकल

यह ट्रेन 26 जनवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक पोरबंदर से प्रस्थान कर गोपजाम जाएगी तथा गोपजाम–कानालुस खंड के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

ट्रेन संख्या 59205 कानालुस–पोरबंदर लोकल

यह ट्रेन 26 जनवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक कानालुस की बजाय गोपजाम स्टेशन से चलेगी और कानालुस-गोपजाम खंड के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

यात्रियों से निवेदन

रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए यात्री वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

तिरुपति लड्डू घी मिलावट कांड में सीबीआई की जांच पूरी, अंतिम चार्जशीट दाखिल होने से कई बड़े नाम घेरे में

(जीएनएस)। अमरावती। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसाद लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी की मिलावट से जुड़े बहुचर्चित मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही सीबीआई की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अपनी विस्तृत जांच पूरी करते हुए स्थानीय अदालत में अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों के अनुसार यह चार्जशीट नेल्लोर की एसीबी अदालत में शुक्रवार को प्रस्तुत की गई, जिसमें तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) से जुड़े कुछ कर्मचारियों, घी आपूर्तिकर्ताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में सामने आए तथ्यों ने इस पूरे मामले की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया है। जांच में पाया गया है कि श्रद्धालुओं की आस्था से सीधे जुड़े प्रसाद निर्माण में इस्तेमाल होने वाले घी में जानबूझकर मिलावट की गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, शुद्ध देसी घी के स्थान पर उसमें पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और पामोलीन जैसे सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले तेलों की मिलावट की गई। इतना ही नहीं, इस मिलावट को छिपाने और जांच एजेंसियों तथा प्रयोगशालाओं को गुमराह करने के लिए रासायनिक पदार्थों का भी इस्तेमाल किया गया। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि मिलावटी घी में बीटा कैरोटीन, एसीटिक एसिड एस्टर, घी फ्लेवर और अन्य कृत्रिम रसायन मिलाए गए थे, ताकि लेबोरेटरी टेस्ट में फैट वैल्यू और अन्य मानक सही प्रतीत हों और घी की खुशबू भी असली जैसी बनी रहे। जांच एजेंसी का मानना है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें गुणवत्ता से समझौता कर आर्थिक लाभ कमाने का प्रयास किया गया और इसके लिए धार्मिक आस्था को भी नजरअंदाज किया गया।

सूत्रों के अनुसार, चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि घी की आपूर्ति प्रक्रिया में कई स्तरों पर लापरवाही और मिलीभगत देखने को मिली। सप्लाई चेन में शामिल कुछ लोगों ने जानबूझकर गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की, जबकि कुछ टीटीडी कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने जांच और निरीक्षण की प्रक्रिया में आंख मूंद ली या फिर जानबूझकर खामियों को नजरअंदाज किया।

सोना वायदा में 13220 रुपये और चांदी वायदा में 35712 रुपये का ऊछालः क्रूड ऑयल में 74 रुपये की तेजी

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 16 से 22 जनवरी के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 3650128.21 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 799478.98 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 2850540.39 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 42989 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 74319.18 करोड़ रुपये का हुआ। आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 671344.78 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 142589 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 158475 रुपये के उच्च और 141220 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 143121 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 13220 रुपये या 9.24 फीसदी की तेजी के संग 156341 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 13720 रुपये या 11.8 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 129968 रुपये प्रति 8 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 1705 रुपये या 11.72 फीसदी की तेजी के संग सप्ताह के अंत में 16247 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 142415 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 158780 रुपये के उच्च और 141184 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 13683 रुपये या 9.58 फीसदी की मजबूती के साथ 156533 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 143131 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 159500 रुपये के उच्च और 142000 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 143406 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 13412 रुपये या 9.35 फीसदी की बढ़त के साथ 156818 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 799478 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 2850540 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 671344 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 42989 पॉइंट के स्तर पर

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 287127 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 335521 रुपये और नीचे में 284045 रुपये पर पहुंचकर, 291577 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 35712 रुपये या 12.25 फीसदी बढ़कर 327289 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 38972 रुपये या 13.28 फीसदी की तेजी के संग 332393 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 38936 रुपये या 13.26 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 332476 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ।

मेटल वर्ग में 41367.59 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 35.45 रुपये या 2.71 फीसदी औंधकर 1273.05 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 5.9 रुपये या 1.86 फीसदी लुढ़ककर 311.95 रुपये प्रति किलो सप्ताह के अंत में बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 3.5 रुपये या 1.1 फीसदी घटकर 315.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 1.85 रुपये या 0.96 फीसदी घटकर 190.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 86732.20 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5357 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 5607 रुपये और नीचे में 5345 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 74 रुपये या 1.38 फीसदी की तेजी के संग 5440 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 74 रुपये या 1.38 फीसदी की बढ़त के साथ 5442 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 246 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 341 रुपये और नीचे में 241.4 रुपये पर पहुंचकर, 244.4 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 82 रुपये या 33.55 फीसदी की तेजी के संग 326.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 81.2 रुपये या 33.21 फीसदी की मजबूती के साथ 325.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा 970 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 14.7 रुपये या 1.51 फीसदी औंधकर 958.7 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 352891.38 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 318453.40 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 35332.99 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 2745.79 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 357.36 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2815.32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7029.96 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 79615.75 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 30.04 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 1.32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11402 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 39495 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 6092 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 69441 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 15754 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9745 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 23106 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 48598 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14671 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 12489 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 38950 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 44301 के उच्च और 38700 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 4176 पॉइंट बढ़कर 42989 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।